



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 1986/आषाढ़ 4, 1908

No. 318]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 1986/ASADHA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 25 जून, 1986

प्रधिसूचनाएं

सा.का.नि. 907(प्र).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 5 की उपधारा (7) द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 20 फरवरी, 1986 की प्रधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309 (प्र) के सिविलिये में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कटक, भवसपुर, जोषपुर और पटना को ऐसे स्थानों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जहाँ 30 जून, 1986 से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, की न्यायपीठें संचालित की जा सकेंगी।

[ए-11019/31(1)/86 ए.टी.]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS  
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 25th June, 1986

NOTIFICATIONS

G.S.R. 907 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training) No. GSR 309 (E) dated the 20th February, 1986 the Central Government

hereby specifies Cuttack, Jabalpur, Jodhpur and Patna as the places at which the Benches of the Central Administrative Tribunal shall ordinarily sit with effect from the 30th June, 1986.

[No. A-11019/31(1)/85-AT]

सा. का. नि. ४०८(अ) :—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिनियम, १९८५ (१९८५ का १३) की धारा १८ की अधि-धारा (१) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार में कामिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक निकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कामिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक २६ जुलाई, १९८५ की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. ६१०(अ) में एतद्वारा दिनांक ३० जून, १९८६ से निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में सारणी के लिए निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:—

#### सारणी

क्रम सं.	न्यायपीठ	न्यायपीठ का क्षेत्राधिकार
१.	प्रधान न्यायपीठ (नई दिल्ली)	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली
२.	इलाहाबाद न्यायपीठ	उत्तर प्रदेश राज्य
३.	बंगलूर न्यायपीठ	महाराष्ट्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य
४.	कलकत्ता न्यायपीठ	सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र।
५.	जम्मूगढ़ न्यायपीठ	जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य तथा जम्मूगढ़ संघ शासित क्षेत्र
६.	फटक न्यायपीठ	उड़ीसा राज्य
७.	बुधगाडी न्यायपीठ	अरुण, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ शासित क्षेत्र
८.	मद्रास न्यायपीठ	केरल तथा तमिल नाडु राज्य तथा लक्षद्वीप तथा माडिगेरी के संघ शासित क्षेत्र
९.	बम्बलपुर न्यायपीठ	मध्य प्रदेश राज्य
१०.	जोधपुर न्यायपीठ	राजस्थान राज्य
११.	नई दिल्ली न्यायपीठ	गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य और दादरा तथा नगर हवेली तथा दीव समूह और दीव संघ शासित क्षेत्र।
१२.	पटना न्यायपीठ	बिहार राज्य

[सं. ए-११०१९/३१(२)/८५-ए.टी.]

जी. वी. अंबे, निदेशक

G.S.R. ५०८(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes, with effect from the 30th June, 1986, the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) No. GSR No. 610(E) dated the 26th July, 1985, namely:—

In the said notification, for the Table the following Table shall be substituted, namely:—

TABLE

Sl. No.	Bench	Jurisdiction of the Bench
1	2	3
1.	Principal Bench, (New Delhi)	The Union Territory of Delhi.
2.	Allahabad Bench	State of Uttar Pradesh.
3.	Bangalore Bench	States of Andhra Pradesh and Karnataka.
4.	Calcutta Bench	States of Sikkim and West Bengal and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

1	2	3
5. Chandigarh Bench		States of Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh and Punjab and the Union territory of Chandigarh.
6. Cuttack Bench		State of Orissa.
7. Guwahati Bench		States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.
8. Madras Bench		States of Kerala and Tamil Nadu and the Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry.
9. Jabalpur Bench		State of Madhya Pradesh.
10. Jodhpur Bench		State of Rajasthan.
11. New Bombay Bench		States of Gujarat and Maharashtra and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu.
12. Patna Bench		State of Bihar

[No. A-11019/31 (2)/85-AT]

P. C. LELE, Director

